PK टाइम्स

लोक टुडे

विश्वसनीय खबरों का सर्वश्रेष्ठ अखबार

pktimesnews.com
loktodaynews.com
PK Times News
thepktimesofficial
pk_timesofficial

वर्ष: 12 | अंक: 311 | मूल्य: 1.00 रुपए | पृष्ठ: 4 | बुधवार 27 मई 2026 | RNI No. RAJHIN/2013/50649

हाईकोर्ट ने अवमानना याचिकाएं खारिज कर सरकार को दी राहत तो 31 जुलाई तक चुनाव करवाना भी बड़ी चुनौती

हाई कोर्ट की दो टूक; राजस्थान में 31 जुलाई तक हर हाल में हो पंचायत-निकाय चुनाव

लोक टुडे। जयपुर

राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अदालत ने चुनाव टालने की मांग और प्रक्रिया से जुड़ी सभी अवमानना याचिकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने पिछले ऐतिहासिक आदेश को बरकरार रखते हुए साफ कर दिया है कि राज्य में 31 जुलाई 2026 तक हर हाल में पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न कराने होंगे। अदालत ने चुनाव टालने के प्रयासों को झटका देते हुए अवमानना याचिकाओं को सुनने से इनकार किया। राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार को 31 जुलाई 2026 की डेडलाइन के भीतर ही प्रक्रिया पूरी करनी होगी। कोर्ट के इस कड़े रुख से स्थानीय निकायों में प्रशासक राज खत्म कर समय पर जन प्रतिनिधि चुनने का रास्ता साफ हुआ है। राजस्थान के ग्रामीण और शहरी सियासी गलियारों में पिछले एक साल से जिस सबसे बड़े चुनावी सस्पेंस ने हर राजनीतिक दल और जमीनी कार्यकर्ताओं की सांसें अटका रखी थीं, उस पर 26 मई को राजस्थान हाई कोर्ट ने पूरी तरह से अंतिम कानूनी मुहर लगा दी है। राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश में समय पर पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के खिलाफ दायर की गई अवमानना याचिकाओं पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ ने इस पूरे मामले की विस्तृत कानूनी समीक्षा करने के बाद याचिकाकर्ताओं की अवमानना याचिकाओं को पूरी तरह से सारहीन घोषित करते हुए खारिज कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने इसके साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को आगामी 31 जुलाई 2026 तक हर हाल में चुनावी प्रक्रिया को पूरा करना ही होगा। इस फैसले के बाद जहां एक तरफ सरकार को अवमानना की कार्रवाई से बड़ी राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ 31 जुलाई की सख्त टाइमलाइन ने प्रशासनिक अमले को पूरी तरह से इलेक्शन मोड में ला खड़ा किया है।

सख्त टाइमलाइन से प्रशासनिक अमला पूरी तरह से इलेक्शन मोड में

दोनों अवमानना याचिकाएं ख़ारिज :

जब इस बेहद संवेदनशील मामले पर जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल और जस्टिस अनिल कुमार उपमन की खंडपीठ के समक्ष अंतिम सुनवाई शुरू हुई, तो अदालत का माहौल पूरी तरह से कानूनी तर्कों से गरमा गया। राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने के लिए खुद राजस्थान के महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद कोर्ट रूम में मौजूद थे। महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने राज्य सरकार का मजबूत पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि सरकार की मंशा चुनाव टालने की कतई नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक मजबूरियों और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट में हो रही देरी के कारण 15 अप्रैल तक चुनाव कराना तकनीकी रूप से संभव नहीं हो सका था। सरकार की ओर से कोर्ट में एक विशेष प्रार्थना पत्र भी पेश किया गया था, जिसमें चुनावी डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। अदालत ने सरकार की दलीलों और बदले हुए घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए पाया कि चूंकि कोर्ट पहले ही अपनी मुख्य रिट याचिका में चुनाव कराने की नई अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 तय कर चुका है, इसलिए अब पुरानी डेडलाइन (15 अप्रैल) को लेकर दायर की गई अवमानना याचिकाओं का कोई कानूनी औचित्य नहीं रह जाता है। इसी आधार पर खंडपीठ ने एडवोकेट प्रेमचंद देवंदा और पुनीत सिंघवी की दलीलों को दरकिनार करते हुए दोनों अवमानना याचिकाओं को पूरी तरह से निस्तारित और समाप्त कर दिया।

सरकार और निर्वाचन आयोग के लिए अब चुनौती :

भले ही सरकार आज अवमानना से बाल-बाल बच गई हो, लेकिन हाई कोर्ट का 31 जुलाई 2026 तक चुनाव संपन्न कराने का आदेश अब भी एक बहुत बड़ी और अचूक लक्ष्मण रेखा की तरह सरकार के सामने खड़ा है। राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि अब चुनाव आयोग और सरकार के पास तैयारियों के लिए महज 40 से 50 दिनों का ही समय बचा है, जो कि सामान्य तौर पर 3 महीने चलने वाली चुनावी प्रक्रिया के लिहाज से बेहद कम है। इस समय सीमा के भीतर चुनाव कराने में मुख्य रूप से प्रशासनिक चुनौतियां सामने आने वाली हैं।

सुरक्षा बलों की भारी कमी का पेंच :

राजस्थान निर्वाचन आयोग के प्रारंभिक आकलन के अनुसार, प्रदेश भर के गांवों और शहरों में एक साथ शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए कम से कम 150000 पुलिसकर्मियों और सुरक्षा बलों की सख्त जरूरत पड़ेगी। जबकि गृह विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, राजस्थान सरकार वर्तमान में केवल 80000 पुलिसकर्मी ही उपलब्ध कराने की स्थिति में है। ऐसे में बाकी की फोर्स पड़ोसी राज्यों या केंद्रीय रिजर्व बलों से मंगवानी होगी, जिसमें एक लंबा समय लगता है।

20 जून तक वोटर लिस्ट का प्रकाशन :

हाई कोर्ट ने अपने निर्देशों में साफ कहा है कि 20 जून 2026 तक सभी ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों के परिसीमन, सीमांकन और अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। हालांकि, निर्वाचन आयोग के सूत्रों का कहना है कि वोटर लिस्ट का काम काफी हद तक पूरा हो चुका है, लेकिन उसे नए सिरे से री-वेरिफाई करने में समय लगेगा।

राजनीतिक पेंच ; ओबीसी कमीशन 20 जून से पहले अंतरिम रिपोर्ट सरकार को सौंपे :

राजस्थान की सियासत को करीब से देखने वाले विश्लेषकों का मानना है कि इस पूरे चुनाव स्थगन के पीछे असली खेल ओबीसी आरक्षण की सीटों के निर्धारण का है। भजनलाल सरकार ने पूर्व में ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग के कार्यकाल को बढ़ाकर आगे कर दिया था, क्योंकि सरकार का तर्क था कि बिना सटीक ओबीसी डेटा के जमीनी स्तर पर सीटों का सही आरक्षण तय करना मुमकिन नहीं है। हाई कोर्ट ने 22 मई के अपने एक अन्य आदेश में ओबीसी कमीशन से साफ कहा है कि वह अपनी अंतरिम रिपोर्ट 20 जून 2026 से पहले सरकार को सौंपे। इसके साथ ही कोर्ट ने एक बेहद तल्ख और तीखी टिप्पणी करते हुए यह भी कह दिया है कि यदि ओबीसी आयोग समय पर अपनी रिपोर्ट सबमिट करने में विफल रहता है, तो निर्वाचन आयोग ओबीसी आरक्षित सीटों को सामान्य सीटें मानते हुए ही 31 जुलाई तक चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करा दे। कोर्ट की इस सख्त लाइन ने सरकार और ओबीसी वर्ग के नेताओं के बीच एक नई बेचैनी पैदा कर दी है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव में जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता। इसके अलावा, बीजेपी सरकार प्रदेश में 'वन स्टेट वन इलेक्शन' यानी पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा पर भी काम कर रही है, जिसके कारण भी व्यवस्थाएं काफी पेचीदा हो गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी और 'दोहरा चरित्र' का आरोप :

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित पूरे विपक्ष ने आरोप लगाया है कि बीजेपी एक तरफ बड़े स्तर पर 'वन नेशन, वन इलेक्शन' की वकालत करती है, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों का सामना करने से डर रही है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि हाईकोर्ट के इस कड़े आदेश के बावजूद भजनलाल सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने और चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए कानूनी रास्ते तलाश रही है। विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, तो वे भी वहां मुस्तैदी से पक्ष रखेंगे ताकि जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों में देरी न हो।

सरकार को राहत, अवमानना का था खतरा :

पिछले साल नवंबर 2025 में राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रदेश की करीब 439 जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए भजनलाल सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को एक कड़ा निर्देश जारी किया था। उस आदेश के तहत सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक वार्डों का परिसीमन और सीमांकन पूरा करना था और किसी भी सूरत में 15 अप्रैल 2026 से पहले चुनाव संपन्न कराने थे। लेकिन जब 15 अप्रैल 2026 की समय सीमा बीत गई और धरातल पर चुनाव नहीं हो सके, तो विपक्ष और याचिकाकर्ताओं ने इसे न्यायपालिका के आदेश की जानबूझकर की गई अवहेलना माना। इसी को आधार बनाकर कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक संयम लोढ़ा और गिर्राज सिंह देवंदा ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की गुहार लगाई थी, जिस पर पिछले महीने हाई कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।

प्रदेश में खेती का डिजिटल कायाकल्प, 95 लाख किसानों को एआई से जोड़ने के लिए समझौता

स्मार्ट होगी खेती, हर पल की मिलेगी लाइव अपडेट, खेत की तस्वीर से पता चल जाएगी बीमारी

लोक टुडे। जयपुर

राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 95 लाख किसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (द्ब) से जोड़ने के लिए एक ऐतिहासिक गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन (स्रश्व) पर हस्ताक्षर किए हैं। जयपुर के पंत कृषि भवन में कृषि विभाग और देश के प्रतिष्ठित नॉट-फॉर-प्रॉफिट संस्थान 'वाधवानी एआई फाउंडेशन' (स्रश्व॥स्) के बीच यह समझौता हुआ है, जिसके तहत किसानों को बिना किसी सरकारी खर्च के अगले 3 वर्षों तक उन्नत तकनीकी सहायता दी जाएगी। ऐसे में अब राजस्थान में खेती-किसानों को सटीक और डेटा आधारित बनाने के लिए भी एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। किसानों को मौसम, फसल, रोग, सिंचाई और कीट प्रबंधन से जुड़ी सलाह समय पर मिल सकेगी। एआई तकनीक से किसानों के खेत, फसल और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर जरूरत के मुताबिक सुझाव मिलेगा। इससे उत्पादन बढ़ाने और नुकसान कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। खबर के लिए हैडिंग

किसानों की बनेगी फार्मर आईडी :

एग्री-स्टैक केंद्र और राज्य सरकारों की डिजिटल कृषि पहल है। इसमें किसानों की जमीन, फसल, खेती के पैटर्न और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाता है। इससे किसानों

को टारगेटेड सेवाएं देने के साथ-साथ सब्सिडी, बीमा और कृषि योजनाओं की मॉनिटरिंग भी आसान होगी। कृषि विभाग के आयुक्त नरेश गोयल ने बताया कि राज्य में एग्री-स्टैक परियोजना के तहत करीब 95 लाख किसानों की 'फार्मर आईडी' तैयार की जा चुकी है। इन आईडी को जमीन रिकॉर्ड और कृषि डेटा से जोड़ा जा रहा है, ताकि किसानों की डिजिटल प्रोफाइल तैयार हो सके। इसी डेटा के आधार पर किसानों तक योजनाओं और सलाह का लाभ सीधे पहुंचाया जाएगा।

खेत की तस्वीर से जान सकेंगे फसल में रोग-कीट :

'एग्रीवाणी' किसानों को स्थानीय भाषा में खेती से जुड़ी सलाह उपलब्ध कराएगा। इसमें मौसम अपडेट, सिंचाई प्रबंधन, उर्वरक उपयोग, कीटनाशक और फसल देखभाल जैसी जानकारियां शामिल होंगी। वहीं, 'क्रोपस' द्ब आधारित इमेज और डेटा एनालिसिस के जरिए फसलों में रोग और कीट की शुरुआती पहचान करेगा। किसान खेत की तस्वीर साझा कर सकेंगे, जिसके आधार पर बीमारी या खतरे का अनुमान लगाकर समाधान भी पता चला जाएगा। इससे फसल खराब होने से पहले ही बचाव संभव हो सकेगा।

सरकार पर नहीं आएगा अतिरिक्त वित्तीय भार :

इसे 'फ्री टेक्नोलॉजी पार्टनर मॉडल' के तहत शुरू किया जा रहा है। तकनीकी सहयोग का सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। अधिकारियों के मुताबिक, इससे कृषि सेवाओं को आधुनिक और तेज बनाने में मदद मिलेगी। राजस्थान में लगातार बदलते मौसम, कम बारिश, पानी की कमी और कीट प्रकोप खेती के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में द्ब आधारित तकनीक मौसम और फसल डेटा का विश्लेषण कर पहले से अलर्ट जारी कर सकेगी। इससे किसान समय रहते फसल बचाव के कदम उठा पाएंगे।

इस पहल से क्या बदलेगा?

इस एआई-संचालित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए यूरिया वितरण और फसल बीमा (PMFBY) जैसी प्रक्रियाओं को बेहद पारदर्शी और आसान बनाया जाएगा। इससे किसानों की लागत कम होगी, फसलों को रोगों से सुरक्षा मिलेगी और राजस्थान में 'स्मार्ट खेती' के एक नए युग की शुरुआत होगी।

अमित शाह बोले- बॉर्डर पर लगेंगे एंट्री ड्रोन सिस्टम

केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने सीमा सुरक्षा बल की सांचू पोस्ट का किया दौरा, बॉर्डर पर जवानों के साथ किया नाश्ता

लोक टुडे। जयपुर

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल (BSF) की सांचू पोस्ट का दौरा किया। इस दौरान प्रहरी सम्मेलन में कहा- मैं ऐतिहासिक चौकी सांचू पर आया हूं। मेरे मन में सांचू चौकी को देखने की इच्छा गृहमंत्री बनने से पहले भी थी। 1964 के भारत-पाक युद्ध में सांचू की आबादी 500 से ज्यादा थी। ड्ढस्ह्र की चौकी 500 मीटर पीछे रणजीतपुरा गांव में थी। सूचना मिली थी कि सांचू पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने शुरुआत की थी। तब 3 ड्ढस्ह्र और 13 ग्रेनेडियर के जवानों ने हमला कर सांचू को भारत की सीमा में रखने का काम किया था। जवानों ने यह जिम्मेदारी निभाई और पाकिस्तानियों को पीठ दिखाकर भागना पड़ा था। उन्होंने कहा- सरकार अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत कर रही है। लेकिन ड्रोन यहां की जमीन पर उतरता है, इसे कौन रिसीव करता है, कौन उसके मटेरियल का उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए। इसके लिए सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। शाह मंगलवार सुबह करीब 11 बजे हेलिकॉप्टर से सांचू पहुंचे थे। उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी थे।

दो बड़ी जंग की गवाह रही सांचू पोस्ट :

भारत-पाकिस्तान बॉर्डर की ये सबसे ऐतिहासिक पोस्ट में शामिल है। ये दो बड़ी जंग की गवाह रही है। अमित शाह पहले गृहमंत्री हैं, जिन्होंने इस पोस्ट पर जाकर जवानों से मुलाकात की। उन्होंने यहां से पाकिस्तानी सरहद और जीरो पॉइंट वाला इलाका भी देखा।

सांचू पोस्ट से देखा पाकिस्तानी इलाका :

सांचू पोस्ट पर अमित शाह ने करीब डेढ़ घंटे बिताए। उन्होंने भीषण गर्मी में ड्यूटी करने वाले जवानों से उनके अनुभव व बॉर्डर एक्टिविटी को लेकर बातचीत की। जवानों के साथ उन्होंने ट्रेडिशनल नाश्ता भी किया। करीब 42 डिग्री टेम्प्रेचर वाली सांचू पोस्ट से अमित शाह ने दूरबीन से आसपास का एरिया भी देखा। इसमें पाकिस्तान बॉर्डर का एरिया भी शामिल है। शाह दोपहर करीब 12.30 बजे बीकानेर के लिए रवाना हुए।

सम्पादकीय

"मानवता सुख शांति प्रेम का, अखिल विश्व में हो
विस्तारस्वतंत्रता का हनन न होवे, रहे सुरक्षित जन अधिकार"

मातृत्व खेल क्षमताओं में बाधक नहीं

खेल की दुनिया में योग्यता-अयोग्यता की कसौटियां कई बार क्षमताओं को बाधित करने या फिर नजरअंदाज करने की हद तक चली जाती हैं। जबकि यह संभव है कि किसी खिलाड़ी को मैदान से बाहर करने के लिए जिन नियमों का हवाला जाता है, उनका कोई खास मतलब नहीं होता है। बस कुछ पूर्वाग्रहों की वजह से नियमों को बहाना बना लिया जाता है और एक सक्षम खिलाड़ी से उसके अवसर छीन लिए जाते हैं।

> दिल्ली हाईकोर्ट ने यह सवाल उठाया कि जब विनेश फोगाट देश की एक स्थापित और शीर्ष स्तर की पहलवान रही हैं, तो नियमों में अचानक बदलाव करके उन्हें खेलने से दूर रखने की कोशिश क्यों की जा रही है!

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इसी प्रवृत्ति पर टिप्पणी करते हुए भारतीय कुश्ती महासंघ को फटकार लगाई और कहा कि हमारे देश में मां बनना कोई गुनाह नहीं है और कुश्ती महासंघ को बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। अदालत ने महिला कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट को एशियाई खेलों के लिए होने वाली चयन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की मंजूरी दे दी है। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट मां बनने के बाद अब फिर से कुश्ती के मैदान में उतरना चाहती हैं, लेकिन भारतीय कुश्ती महासंघ ने डोपिंग-रोधी नियमों का हवाला देते हुए विनेश फोगाट को 26 जून तक घरेलू प्रतियोगिताओं में खेलने के 'अयोग्य' घोषित कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह सवाल उठाया कि जब विनेश फोगाट देश की एक स्थापित और शीर्ष स्तर की पहलवान रही हैं, तो नियमों में अचानक बदलाव करके उन्हें खेलने से दूर रखने की कोशिश क्यों की जा रही है! गौरतलब है कि विनेश फोगाट को भारत की सबसे कामयाब महिला पहलवानों में से एक माना जाता है। 2024 के पेरिस ओलंपिक में एक तकनीकी वजह से उनके करिअर में चुनौती सामने आई थी, लेकिन उससे पार निकल कर उन्होंने आगे का रास्ता देखा। कुछ समय पहले वे मां बनीं और मातृत्व अवकाश की वजह से वे थोड़े वक्त के लिए खेल से दूर रहीं। मगर यह उनके मैदान से बाहर होने का कारण नहीं हो सकता। दुनिया भर में ऐसे तमाम उदाहरण हैं, जिसमें महिला खिलाड़ियों ने मां बनने के बाद भी खेल के मैदान में बेहतरीन प्रदर्शन किया और उपलब्धियां हासिल कीं। यों यह समय-समय पर साबित होता रहा है कि मातृत्व खेल क्षमताओं में बाधक नहीं है। बेहतर हो कि पूर्वाग्रहों या बदले की भावना के बजाय किसी खिलाड़ी की योग्यता का आकलन खेल में उसके सक्षम होने के आधार पर हो।

पश्चिम एशिया संकट के बीच क्वाड बैठक पर टिकी दुनिया की नजरें

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच फिलहाल युद्धविराम जारी है, लेकिन होर्मुज जलमार्ग को खुलवाने के लिए अमेरिका के प्रयास अभी तक नाकाम रहे हैं।

पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष से गहरा रहे वैश्विक संकट के बीच क्वाड देशों की महत्त्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। खास बात यह है कि भारत की मेजबानी में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यह बैठक होगी। खबरों के मुताबिक, इस बैठक में हिंद-प्रशांत क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर विचार-विमर्श के अलावा विश्व भर में पैदा हुए ऊर्जा संकट से निपटने के उपायों पर भी मंथन किया जाएगा। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन दौरे को लेकर भी यह उम्मीद जताई जा रही थी कि पश्चिम एशिया में शांति बहाली का कोई रास्ता निकलेगा, मगर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की वार्ता के नतीजे में ऐसा कुछ नजर नहीं आया। क्वाड में शामिल देशों में से भारत पर इस वैश्विक संकट का मौजूदा परिस्थितियों में सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। चूंकि वर्तमान में भारत क्वाड की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए यह उम्मीद है कि इस बैठक में ऊर्जा संकट का मसला प्रमुखता से रखा जाएगा। यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि क्वाड में अमेरिका भी शामिल है और ईरान के साथ उसके और इजरायल के संघर्ष से ही संकट की यह स्थिति उत्पन्न हुई है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने शनिवार को भारत पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं, विशेषकर रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग बढाने पर विचार-विमर्श किया। साथ ही पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की गई। अब सबकी नजरें क्वाड की बैठक पर टिकी हैं कि उसमें किन मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा की जाएगी। अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच फिलहाल युद्धविराम जारी है, लेकिन होर्मुज जलमार्ग को खुलवाने के लिए अमेरिका के प्रयास अभी तक नाकाम रहे हैं। इसके बजाय होर्मुज के आसपास अमेरिका की नाकेबंदी से स्थिति और जटिल हो गई है। दोनों देश अपनी-अपनी शर्तों पर अड़े हैं, जिस कारण शांति वार्ता के मार्ग पर अनिश्चितता की बर्फ जम गई है। यही वजह है कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा समेत अन्य आवश्यक वस्तुओं की कमी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। पश्चिम एशिया में संघर्ष से उपजे वैश्विक संकट का भारत पर कितना असर हुआ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दस दिनों से भी कम समय में शनिवार को तीसरी बार बढ़ोतरी की गई। पेट्रोल के दाम में 87 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल में 91 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। सीएनजी की कीमत में भी एक रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई है। जाहिर है कि ईंधन के दामों में इजाफे से आने वाले दिनों में रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुएं भी महंगी होंगी। कुल मिलाकर इस संकट की सबसे ज्यादा मार आमजन पर ही पड़ेगी। इसलिए जरूरी है कि क्वाड की बैठक में इस मसले को प्रमुखता से रखा जाए और संकट का स्थायी समाधान तलाशने की कोशिश की जाए। इस संगठन में भारत, अमेरिका के अलावा आस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं और यह हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक प्रमुख समूह के रूप में उभरा है। क्वाड की इस बैठक को इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि इसमें समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और संपर्क सुविधा जैसे मसलों पर गहन मंथन किए जाने की संभावना है।

वैश्विक थपेड़ों से जूझता रुपया

शिवकांत शर्मा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहले देशवासियों से ऊर्जा की किफायत करने की अपील की और फिर चेतावनी दी कि पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के कारण दुनिया में आर्थिक मंदी आ सकती है। उनके वक्तव्यों के पीछे चार चिंताएं काम कर रही थीं। होर्मुज जलमार्ग बंद होने से तेल, गैस और खाद के दाम डेढ़ गुना से अधिक हो गए जिसके कारण भारत का ऊर्जा और खाद आयात बिल लगभग डेढ़ गुना हो गया है। ऊर्जा और खाद के दाम बढ़ने से देश में महंगाई बढ़ने और बजट गड़बड़ाने का खतरा पैदा हो गया है। विदेशी निवेशक पिछले दो साल से भारत से अपनी पूंजी निकाल रहे हैं और अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के आसार से इसकी रफ्तार और तेज हो सकती है। ऊर्जा और खाद के आयात का बिल बढ़ने और विदेशी पूंजी के पलायन से रुपया सस्ता हो रहा है, जिसकी वजह से आयात महंगे होते जा रहे हैं।

डालर की तुलना में रुपया दशकों से गिर रहा है जिसकी रफ्तार पिछले दशक में और बढ़ी है और वह 66 से गिरकर 96 पर जा पहुंचा है। इसमें से 6.1 प्रतिशत की गिरावट ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद से हुई है। रुपया डालर की तुलना में ही नहीं, बल्कि जापानी येन को छोड़कर लगभग हर हार्ड करेंसी की तुलना में कमजोर पड़ा है। पिछले साल भर में तो वह पाकिस्तानी रुपये और बांग्लादेशी टके की तुलना में भी 10 प्रतिशत से अधिक गिरा, जिसकी वजह से भारत में मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि पाकिस्तानी रुपये का ग्राफ देखें तो उसका भाव 2016 से 2024 के बीच डालर की तुलना में भारतीय रुपये से दोगुनी रफ्तार के साथ गिरा है। 2022 से 2024 के बीच बांग्लादेशी टके की भी यही हालत हुई। 2024 के बाद पाकिस्तानी रुपये और बांग्लादेशी टके की दरों में तो थोड़ी स्थिरता आई, लेकिन भारतीय रुपये के गिरने की रफ्तार कहीं तेज रही। रुपये की तुलना में इन दोनों मुद्राओं की कीमत में थोड़ा सुधार दिखाई देने की असली वजह यही है। हकीकत यही है कि मुद्रा की विनिमय दर किसी देश की अर्थव्यवस्था की ताकत या कमजोरी का पैमाना नहीं होती। मिसाल के तौर पर जापानी येन का भाव इस समय लगभग 60 पैसे है। तो क्या भारत की अर्थव्यवस्था जापान से डेढ़ गुना मजबूत मान ली जाए? इसी तरह यूरो आने से पहले 1998 में एक रुपया 40 इतालवी लीरा का होता था। तो क्या भारत इटली से चालीस गुना विकसित था? किसी देश की मुद्रा की कीमत उसकी जीडीपी और जारी मुद्रा की संख्या के आधार पर तय होती है और विनिमय दर मुद्रा की मांग के आधार पर चढ़ती-गिरती है। जिस देश का निर्यात आयात से अधिक होता है और जिसकी मुद्रा को लोग निवेश के लिए जमा रखना चाहते हैं, उसकी मांग बढ़ती है। परिणामस्वरूप उसकी विनिमय दर भी बढ़ती है। हालात इसके उलट होने पर मुद्रा की मांग घटती है और विनिमय दर भी गिर जाती है। इसलिए न तो मुद्रा झंडे की तरह देश की आन होती है और न ही उसकी अर्थव्यवस्था का पैमाना। भारत में सकल एफडीआइ या विदेशी निवेश की मात्रा में कमी नहीं आ रही। वह लगातार बढ़ रही है, लेकिन भारत से वापस जाने वाले विदेशी निवेश की मात्रा भी पिछले तीन सालों से बढ़ रही है। इसके दो कारण बताए जाते हैं। एक तो विदेशी निवेशक उन बाजारों का रुख कर रहे हैं जहां एआइ, सेमीकंडक्टर और डाटा के क्षेत्रों में नए आविष्कार हो रहे हैं। इन कंपनियों के दाम डाट-काम के दिनों की तरह हफ्तों के भीतर दोगुने-तिगुने होते जा रहे हैं। हालांकि बड़े विदेशी निवेशकों के लिए अपना निवेश एक साथ बेचना आसान नहीं होता, क्योंकि बेचने की भनक पड़ते ही दाम और मुनाफा गिरने लगता है। विडंबना इस बात की है कि उनकी यह मुश्किल भारत में लोकप्रिय हुए म्यूचुअल फंडों ने आसान की है। अमेरिकी निवेश बैंक जेफरीज का कहना है कि म्यूचुअल फंडों के जरिये निवेश करने वाले भारतीय निवेशकों की मांग की आड़ में विदेशी निवेशक अपना पैसा शेयर बाजार में गिरावट लाए बिना निकाल कर वहां लगा रहे हैं, जहां एक महीने में उतना मुनाफा मिल रहा है जो भारत में एक साल में नहीं मिलता। दूसरा कारण खाड़ी से पैदा हुआ ऊर्जा संकट है, जिससे भारत का बजट गड़बड़ाने, व्यापार घाटा और महंगाई बढ़ने और रुपया गिरने का खतरा पैदा हो गया है। रुपया गिरने से विदेशी निवेशकों के निवेश की कीमत भी गिरती है। इसीलिए वे भाग रहे हैं। रुपया गिरने से सरकार पर राजनीतिक दबाव भी पड़ता है, जिसे कम करने के लिए रिजर्व बैंक डालर बेचकर रुपये को सहारा देने की कोशिश कर सकता है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व उपनिदेशक गीता गोपीनाथ का कहना है कि रिजर्व बैंक को अपना लगभग 700 अरब डालर का विदेशी मुद्रा भंडार रुपया उबारने में बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सस्ता रुपया भारत के निर्यातकों को लाभ पहुंचाएगा। वे विदेशी मंडियों में कड़ी प्रतिस्पर्धा देकर अधिक माल बेच सकेंगे, जिससे विदेशी मुद्रा की आमद बढ़ेगी। हालांकि इसका दूसरा और राजनीतिक रूप से जोखिम भरा पहलू यह है कि रुपया सस्ता होने से आयात महंगे होंगे, जिनमें तेल और खाद प्रमुख हैं। इनसे हर चीज महंगी होगी और विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है।

तेल कंपनियों को प्रतिदिन हो रहे 750 करोड़ रुपये के घाटे को कम करने के लिए यदि पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ाए गए तो उससे मिली राहत से रुपये की गिरावट बेअसर हो जाएगी। इसलिए नीति आयोग के पूर्व प्रमुख अमिताभ कांत का कहना है कि इस संकट को अवसर में बदलकर उन कार्यों को पूरा करना चाहिए, जो हमें जलवायु रक्षा के लिए करने चाहिए थे। तेल और खाद के बढ़े हुए दामों से लोग दोनों की किफायत करने और स्वच्छ ऊर्जा अपनाने को विवश होंगे। इससे जलवायु को बेहतर बनाने के साथ-साथ एआइ, ऊर्जा और डाटा भंडारण के क्षेत्रों में नई खोजों की प्रेरणा मिलेगी। असल में रुपये को स्थायी रूप से तभी उबारा जा सकता है जब निर्यात और विदेशी निवेश बढ़ें। ये दोनों काम आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के बिना नहीं हो सकते।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर एक नया रणनीतिक मोड़: बाड़ लगाना, एन्क्लेव विवाद और 'चिकन नेक' को सुरक्षित करने का महा-मिशन

लेखक: कर्नल देव आनंद लोहमरोड़ (सुरक्षा एवं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ)...

1971 में बांग्लादेश के उदय के बाद, एक जटिल 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा अस्तित्व में आई। इस सीमा को व्यवस्थित करने के लिए, 16 Fil मई 1974 को भूमि सीमा समझौता (LBA) किया गया, जिसे 1975 में मान्यता मिली। इसकी सबसे बड़ी व्यावहारिक विसंगति 162 एन्क्लेव (अंत:क्षेत्र/विदेशी क्षेत्र) की उपस्थिति थी—जिसमें भारत के भीतर 111 बांग्लादेशी एन्क्लेव और बांग्लादेश के भीतर 51 भारतीय एन्क्लेव शामिल थे। ये इलाके तस्करी, घुसपैठ और जाली नोटों (FICN) के अनियंत्रित ठिकाने बन गए थे। इस ऐतिहासिक भूल को सुधारने के लिए, भारत सरकार ने 2015 में 100वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से क्षेत्रों का आदान-प्रदान कर सीमा को स्थायी रूप से निर्धारित किया। ?आज, यह पूर्वी सीमा एक बड़े रणनीतिक बदलाव से गुजर रही है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर ('चिकन नेक') और इसके आस-पास के सीमावर्ती जिले भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं के केंद्र में आ गए हैं। गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सीमा को पूरी तरह से अभेद्य बनाने के स्पष्ट निर्देश के बाद, ग्राउंड ज़ीरो पर इसके ठोस परिणाम दिखने लगे हैं। फिर भी, स्थानीय गतिरोधों के साथ-साथ, चीन, पाकिस्तान और बदलते बांग्लादेशी नेतृत्व को शामिल करने वाला एक गहरा त्रिपक्षीय भू-राजनीतिक समीकरण सतह पर आने लगा है, जो दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन के लिए चुनौती बना हुआ है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के कूचबिहार सेक्टर में भारी सैन्य तनाव देखा गया, जहाँ बीएसएफ की सुरक्षा में एक भारतीय राजस्व दल (अमीनों) ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास 27 किलोमीटर के संवेदनशील और असुरक्षित हिस्से को सील करने के लिए भूमि सर्वेक्षण और पिलर लगाने का काम शुरू किया था। इस काम में स्थानीय बांग्लादेशी नागरिकों ने व्यवधान डाला, जिन्हें बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश (BGB) के सशस्त्र कर्मियों का समर्थन प्राप्त था। कूचबिहार बांग्लादेश के साथ 500 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, जिसमें से 50 किलोमीटर का हिस्सा ऐतिहासिक रूप से बिना बाड़ के और असुरक्षित रहा है, जिससे सीमा पार अपराधों को बढ़ावा मिलता है। यहाँ दहाग्राम-अंगारपोता एन्क्लेव स्थित है, जो तीस्ता नदी के मुहाने के पास भारत के भीतर घिरा एकमात्र प्रमुख बांग्लादेशी क्षेत्र है। यह मुख्य भूमि बांग्लादेश से भारतीय क्षेत्र की महज 178 मीटर लंबी एक संकरी पट्टी के माध्यम से जुड़ता है, जिसे 'तीन बीघा कॉरिडोर' के रूप में जाना जाता है, जिसे भारत ने प्रशासनिक पहुंच के लिए ढाका को पट्टे (लीज़) पर दिया था। विवाद तब भड़का जब भारतीय टीम ने जीरो पॉइंट (सीमा रेखा) से 50 फीट अंदर संप्रभु क्षेत्र में सीमा पिलर स्थापित किए, जिस पर बीजीबी यूनिट के एक अधिकारी ने कड़ा विरोध जताते हुए दावा किया कि जीरो पॉइंट से 150 गज (लगभग 450 फीट) के दायरे में 'नो कंस्ट्रक्शन ज़ोन' लागू होता है, जो भारत को पिलर लगाने से रोकता है। हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानदंडों और 1974-75 के समझौतों के तहत, यह प्रतिबंध विशेष रूप से सामरिक सैन्य बंकरों या सैन्य चौकियों जैसे स्थायी रक्षात्मक ढांचों पर लागू होता है, न कि सुरक्षात्मक बुनियादी ढांचे पर। चूंकि कंटीली बाड़ लगाना सार्वभौमिक रूप से एक गैर-स्थायी, सुरक्षात्मक उपाय के रूप में वर्गीकृत है जो सैन्य आक्रामकता के लिए नहीं बल्कि अपराध की रोकथाम के लिए है, इसलिए भारत के पास अपनी सीमा रेखा तक अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने का पूर्ण संप्रभु अधिकार है।

2015 के एलबीए (LBA) की ऐतिहासिक सफलता के बावजूद, जमीन पर कंटीली बाड़ लगाने का काम अभी भी गंभीर मानवीय और सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। यदि सीमा इंजीनियर जीरो लाइन से ठीक 150 गज की दूरी पर कड़े गणितीय नियमों के साथ बाड़ लगाते हैं, तो बसे हुए भारतीय सीमावर्ती गांवों के पूरे हिस्से और विशाल कृषि क्षेत्र बाड़ के गलत तरफ छूट जाते हैं—जो हाई-सिक्योरिटी बाड़ और वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बीच एक कानूनी नो-मैन-लैंड में फंस जाते हैं। इन सीमावर्ती आबादी की मानवीय वास्तविकताएं आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं; पीढ़ियों से स्थानीय जीवनशैली ऐसी रही है जहां परिवारों के सीमा पार गहरे संबंध हैं, लोग अक्सर सीमा के एक तरफ रात का खाना खाते हैं और अगली सुबह खेती के लिए खुले खेतों से दूसरी तरफ चले जाते हैं।

इसलिए, वर्तमान सीमा बुनियादी ढांचा अभियान को केवल एक ठंडे, यांत्रिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट या विशुद्ध सैन्य अभ्यास के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह एक अत्यंत संवेदनशील, जटिल सामाजिक-राजनीतिक मिशन बन चुका है। भारतीय राज्य को मानवीय सहानुभूति के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं को लगातार संतुलित करना पड़ रहा है—जिसमें जटिल भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को संभालना, भारी वित्तीय मुआवजा प्रदान करना और विस्थापित सीमावर्ती नागरिकों के लिए वैकल्पिक कृषि भूमि की व्यवस्था करना शामिल है। बहरहाल, जैसा कि इतिहास गवाह है, जब राज्य पूर्ण दृढ़ता दिखाता है, अपनी प्रशासनिक मशीनरी का पूरा उपयोग करता है और स्पष्ट सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करता है, तो काम सुचारू रूप से पूरा हो जाता है। ?एक तरफ जहां भारत आक्रामक रूप से अपनी आंतरिक क्षेत्रीय संप्रभुता को मजबूत कर रहा है, वहीं उसकी पूर्वी सीमाओं के ठीक पार एक अत्यधिक समन्वित और खतरनाक सामरिक संरेखण (alignment) तेजी से आकार ले रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ और वायु सेना के प्रतिनिधिमंडलों की ढाका की आगामी आधिकारिक यात्रा, और ठीक उसी समय बांग्लादेशी राजनीतिक नेतृत्व (तारिक रहमान) की बीजिंग की आगामी उच्च स्तरीय यात्रा, कोई सामान्य क्षेत्रीय कूटनीति नहीं बल्कि एक सोची-समझी त्रिपक्षीय रणनीतिक चाल है। इस्लामाबाद और ढाका के बीच उभरता हुआ यह अक्ष अब सक्रिय सैन्य सहयोग के दायरे में प्रवेश कर चुका है। दोनों देशों के उच्च स्तरीय सैन्य प्रतिनिधिमंडल वर्तमान में उन्नत सैन्य हार्डवेयर की खरीद पर केंद्रित समझौतों को अंतिम रूप दे रहे हैं—जिसमें बांग्लादेश अपने पुराने विमानों को बदलने के लिए संयुक्त चीनी-पाकिस्तानी जेएफ-17 थंडर (JF-17 Thunder) लड़ाकू विमानों को खरीदने की सक्रिय चर्चा कर रहा है। इसके साथ ही उन्नत लड़ाकू पायलट कार्यक्रमों के लिए सामरिक प्रशिक्षण और बांग्लादेश के घरेलू रक्षा औद्योगिक परिसर को तेजी से आधुनिक बनाने के लिए संयुक्त ड्रोन निर्माण व कम दूरी की मिसाइल उत्पादन के लिए गहरी तकनीक के हस्तांतरण पर भी बात चल रही है। इसी के साथ, बीजिंग बड़े पैमाने पर तीस्ता नदी व्यापक प्रबंधन परियोजना (Teesta River Comprehensive Management Project) के वित्तपोषण और क्रियान्वयन के माध्यम से अपने रणनीतिक प्रभाव का विस्तार कर रहा है। यह मेगा-इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ठीक बगल में स्थित है, जो एक ऐसा अग्रिम लिसनिंग पोस्ट (listening post) स्थापित करता है जहां नई दिल्ली किसी भी सूरत में शत्रुतापूर्ण चीनी खुफिया, निगरानी और जासूसी उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ?भारत के साउथ ब्लॉक—जिसमें विदेश मंत्रालय (MEA) और रक्षा मंत्रालय (MoD) शामिल हैं—के वरिष्ठ नीति निर्माताओं की मेजें वर्तमान में इस समन्वित त्रिपक्षीय खतरे की विस्तृत और अत्यंत गोपनीय खुफिया फाइलों से भरी हुई हैं। ढाका में पाकिस्तानी वायु सेना के प्रतिनिधिमंडलों का जमावड़ा, रणनीतिक चोकपॉइंट्स (सँकरे रास्तों) के पास चीनी राज्य समर्थित भारी बुनियादी ढांचा निवेश और सीमावर्ती जिलों में सोए हुए चरमपंथी नेटवर्क का अचानक सक्रिय होना, ये सभी रिपोर्टें एक ही समय में एक ही डेस्क पर पहुंच रही हैं। अवैध घुसपैठ के खिलाफ एक भौतिक सीमा को सील करना एक सामरिक सीमा प्रबंधन की समस्या है; लेकिन भारत की पूर्वोत्तर तक पहुंच को रोकने के लिए बनाई गई एक सुनियोजित, त्रिपक्षीय रणनीतिक घेराबंदी का जवाब देना पूरी तरह से एक अलग और अत्यधिक जटिल भू-राजनीतिक खेल है। नई दिल्ली वर्तमान में एक अत्यंत कूटनीतिक सीमा नीति लागू कर रही है जो दोहरे सिद्धांत पर आधारित है: 'सीमा पर कड़े, मेज पर नरम (Tough at the border, Warm at the table) '। एक तरफ, सरकार का मुख्य राजनीतिक आधार जमीन पर पूर्ण और प्रत्यक्ष दृढ़ता की मांग करता है—जिसकी पहचान स्मार्ट बाड़ का अटूट उपयोग, बीजीबी (BGB) के उकसावे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और प्रत्येक अवैध घुसपैठिये की व्यवस्थित पहचान और निर्वासन है। दूसरी तरफ, व्यापक भू-राजनीतिक ताना-बाना चाहता है कि भारत कूटनीतिक स्तर पर ढाका के साथ द्विपक्षीय बातचीत की मेज पर गर्मजोशी और जुड़ाव बनाए रखे। नई दिल्ली को ढाका में नए राजनीतिक नेतृत्व के सामने ठोस सहयोगात्मक पहल, आर्थिक साझेदारी और पारस्परिक रूप से सहमत ढांचे—जैसे कि तीस्ता जल-बंटवारे के प्रस्ताव को सक्रिय रूप से मेज पर बनाए रखना—की पेशकश जारी रखनी होगी। यह बांग्लादेश को एक व्यावहारिक विकल्प प्रदान करने के लिए आवश्यक है, ताकि उसे स्थायी रूप से और अपरिवर्तनीय रूप से शत्रुतापूर्ण चीन-पाकिस्तान सैन्य धुरी में जाने से रोका जा सके। सीमा पर सैन्य प्रतिरोध और राजधानी में परिष्कृत कूटनीति के बीच इस नाजुक एवं उच्च-जोखिम वाले संतुलन को साधना ही अंततः आने वाले दशकों के लिए दक्षिण एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे और भू-राजनीतिक भविष्य को तय करेगा।

आभासी रिश्तों की भीड़ में खोता वास्तविक अपनापन

परमानन्द गोयल

आज के दौर में हम 'कनेक्टेड' तो बहुत हैं, लेकिन वास्तव में 'जुड़े' हुए नहीं हैं। तकनीक ने दुनिया को मुट्ठी में समेट दिया है, पर दिलों के बीच की दूरियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं। डिजिटल क्रांति के इस युग में स्मार्टफोन और इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक 'वैश्विक गाँव' में बदल दिया है। हमारी मित्रता, संवेदनाएँ और संवाद अब एक क्लिक तक सीमित होकर रह गए हैं। लेकिन इस चमकती आभासी दुनिया के पीछे एक कड़वा सच भी छिपा है—हम एक-दूसरे के करीब नहीं आ रहे, बल्कि केवल सूचनाओं का आदान-प्रदान कर रहे हैं।

'लाइक' की भीड़ में अकेला इंसान

आभासी दुनिया का आकर्षण असंदिग्ध है। सोशल मीडिया पर मिलने वाले सैकड़ों 'लाइक' और 'कमेंट' क्षणिक खुशी तो देते हैं, लेकिन वे आत्मीयता का विकल्प नहीं बन सकते। आज हमारे डिजिटल मित्रों की संख्या हजारों में हो सकती है, पर जीवन के कठिन मोड़ों पर साथ खड़े होने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं।

जन्मदिन पर हजारों शुभकामना संदेश मिल जाते हैं, लेकिन कंधे पर हाथ रखकर हौसला देने वाला

अपनापन कहीं खोता जा रहा है। हमने संपर्क तो बढ़ा लिया, पर संबंध की गहराई धीरे-धीरे कम होती चली गई।

डाइनिंग टेबल पर पसरा सन्नाटा

आज परिवार एक ही घर में रहते हुए भी अलग-अलग स्क्रीन में कैद होता जा रहा है। डाइनिंग टेबल पर संवाद की जगह मोबाइल ने ले ली है। आत्मीय मुलाकातों की जगह वीडियो कॉल और इमोजी ने संबंधों को औपचारिक बना दिया है। वास्तविक रिश्तों को समय, धैर्य और भावनात्मक निवेश की आवश्यकता होती है, लेकिन तेज़ रफ्तार जीवनशैली में हम इन सबसे बचने लगे हैं। तकनीक सुविधा तो दे सकती है, लेकिन वह उस मानवीय स्पर्श का विकल्प कभी नहीं हो सकती, जो किसी अपने के साथ बैठने, मुस्कुराने या गले मिलने से महसूस होता है। सोशल मीडिया की 'परफेक्ट लाइफ' की चमक कई लोगों में हीनभावना, तनाव और अकेलेपन को भी बढ़ा रही है।

संतुलन की अनिवार्य आवश्यकता

समस्या तकनीक में नहीं, बल्कि उसके अति-उपयोग और उस पर बढ़ती निर्भरता में है। जब आभासी दुनिया वास्तविक जीवन पर हावी होने लगे, तब यह समझ लेना चाहिए कि हम धीरे-धीरे अपनी जड़ों से कट रहे हैं। समय की आवश्यकता है कि हम 'डिजिटल डिटॉक्स' अपनाएँ, स्क्रीन टाइम सीमित करें और परिवार व मित्रों के साथ आमने-सामने संवाद को प्राथमिकता दें। रिश्तों को केवल ऑनलाइन उपस्थिति नहीं, बल्कि भावनात्मक उपस्थिति की भी आवश्यकता होती है।

निष्कर्ष : तकनीक साधन है, साध्य नहीं

हमें तकनीक और आत्मीयता के बीच एक संतुलित रेखा खींचनी होगी। बुजुर्गों के अनुभव सुनने, बच्चों के साथ खेलने और मित्रों से व्यक्तिगत रूप से मिलने का कोई डिजिटल विकल्प नहीं हो सकता। याद रखिए, वास्तविक रिश्ते जीवन की वह अमूल्य पूंजी हैं जिन्हें केवल 'रिचार्ज' नहीं, बल्कि प्रेम, समय और संवेदनाओं से निरंतर 'सींचना' पड़ता है। यदि हम संबंधों की गर्माहट को बचाए रख सके, तभी हमारी मानवीय संवेदनाएँ जीवित रह पाएँगी। अन्यथा, इंसानों की इस भीड़ में हम केवल एक 'प्रोफाइल' बनकर रह जाएँगे।

अधिकारियों की बैठक मुख्यमंत्री ने भरतपुर में ली जिलास्तरीय अधिकारियों की बैठक

भीषण गर्मी में पेयजल, बिजली और चिकित्सा व्यवस्थाओं को करें और अधिक सुदृढ़:मुख्यमंत्री

जयपुर(नि.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भरतपुर में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि भरतपुर हमारी ऐतिहासिक विरासत है, इसलिए विकास और धरोहर संरक्षण के कार्य बेहतर कार्ययोजना के साथ सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने के साथ ही फील्ड विजिट बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भीषण गर्मी के दृष्टिगत पेयजल, बिजली और चिकित्सा व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जाए, ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में टैंकर व्यवस्था तथा पेयजल आपूर्ति को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को विभागीय योजनाओं में लंबित प्रकरणों के संदर्भ में संबंधित संवेदकों और ठेकेदारों पर पेनल्टी लगाने और धारा 91 के तहत रिपोर्ट भिजवाने के लिए निर्देशित भी किया। उन्होंने जिले में सुचारू एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति की समीक्षा करते हुए ट्रांसफार्मर के लोड फिक्सेशन और नए ट्रांसफार्मर लगाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने सीएचसी और पीएचसी में आवश्यक दवाइयों की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करने, गर्मी से बचाव के लिए आमजन को जागरूक करने तथा फूड इंस्पेक्टरों को औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आमजन को बुनियादी सेवाएं और सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी और कार्मिक टीम भावना के साथ कार्य करें।

प्राचीन कुंडों का करें पुनरुद्धार

मुख्यमंत्री ने कहा कि भरतपुर की भौगोलिक स्थिति कटोरे के समान है, इसलिए बरसात के समय जलभराव की समस्या से निपटने के लिए अधिकारी बेहतर प्लानिंग करें। उन्होंने जिला कलेक्टर को निर्देश दिए कि एक विशेष टीम गठित कर शहर की सड़कों पर जलभराव के कारणों का मुआयना करें और स्थायी समाधान निकालें। उन्होंने शहर के प्राचीन कुंडों का पुनरुद्धार और पौधारोपण के संबंध में भी विस्तृत दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिले में एनीकट, नहरों और पोखरों का जीर्णोद्धार करने तथा कच्ची नहरों की सफाई सुनिश्चित की जाए।

प्रभारी सचिव शिवांगी स्वर्णकार ने की जिला स्तरीय योजनाओं की समीक्षा

सवाई माधोपुर जिले में जलापूर्ति, बिजली, स्वास्थ्य सेवाओं एवं बजट घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर

जयपुर (नि.सं.)। प्रभारी सचिव शिवांगी स्वर्णकार ने सोमवार को सवाई माधोपुर जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं, बजट घोषणाओं, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं एवं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में जिला कलक्टर काना राम, उप वन संरक्षक मानस सिंह सहित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रभारी सचिव ने ग्रीष्मकालीन पेयजल व्यवस्था एवं समर कंटीजेंसी प्लान की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आमजन को निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

अधिक्षण अभियंता बी.एस. मीणा ने बताया कि जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में समर कंटीजेंसी के तहत स्वीकृत कार्य प्रगति पर हैं तथा हैंडपंप मरम्मत अभियान के माध्यम से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में 930 से अधिक एवं शहरी क्षेत्रों में 100 से अधिक खराब हैंडपंपों को प्राथमिकता से दुरुस्त किया गया है। जल जीवन मिशन के तहत संचालित परियोजनाओं पर भी चर्चा कर प्रभारी सचिव ने कार्यों की गुणवत्ता एवं समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करने एवं पूर्ण हो चुकी सभी जल जीवन परियोजनाओं का 26 मई को ग्राम सभाओं के दौरान सत्यापन करवाने के निर्देश दिए। बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर-बैठक में वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 की बजट घोषणाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए प्रभारी सचिव ने निर्देश दिए कि जिन घोषणाओं पर कार्य प्रगति पर है, उन्हें निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाए तथा जिन प्रस्तावों पर कार्यवाही लंबित है, उनमें तेजी लाई जाए।

न्यूज इन बॉक्स

जयपुर में होगी स्टूडेंट फिल्म मेकिंग वर्कशॉप

युवाओं को मिलेगा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने का मौका

जयपुर (नि.सं.)। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज और इंडो इंटरनेशनल फिल्म फाउंडेशन ऑफ कल्चर एंड आर्ट्स फेडरेशन ने जयपुर में एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। दोनों संस्थाओं की ओर से संयुक्त रूप से आत्मनिर्भर विद्यार्थी अभियान - स्टूडेंट फिल्म मेकिंग वर्कशॉप और आईआईएफएफसीए फिल्म फेस्टिवल-2026 आयोजित किया जाएगा। आयोजक दिव्यांक शर्मा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, युवा फिल्म निर्माताओं, कंटेंट क्रिएटर्स और मीडिया क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं को फिल्म निर्माण की तकनीकी और व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध कराना है। साथ ही उन्हें इंडस्ट्री विशेषज्ञों से सीखने और अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर भी मिलेगा। इसके तहत 21 जून को एक दिवसीय सेमिनार और 25 जून से जयपुर में 12 दिवसीय स्टूडेंट फिल्म मेकिंग वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा।

महिला उद्यमी समूह 'फेमप्रेन्योर' के नए कार्यकाल की शुरुआत

'लॉन्च मीट एंड ग्रीट' कार्यक्रम में जुटीं शहर की बिजनेस वुमन, कार्यक्षेत्र के अनुभवों को किया शेयर

जयपुर(नि.सं.)। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और महिलाओं को एक मजबूत नेटवर्किंग मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एफबीएस जयपुर के महिला उद्यमी समूह 'फेमप्रेन्योर' के नए कार्यकाल की शुरुआत उत्साह और ऊर्जा के साथ की गई। वैशाली नगर स्थित आउट जयपुर में आयोजित फेमप्रेन्योर लॉन्च मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण, प्रेरणा और नए अवसरों के साझा मंच के रूप में यादगार बन गया। कार्यक्रम में शहर की कई प्रेरणादायक महिला उद्यमियों ने भाग लिया। इस दौरान प्रतिभागियों ने एक-दूसरे से मुलाकात कर अपने व्यवसाय, कार्यक्षेत्र और अनुभवों को साझा किया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना था, जहां वे नेटवर्किंग के साथ-साथ एक-दूसरे को प्रेरित करते हुए सामूहिक रूप से आगे बढ़ सकें।

राष्ट्रपति भवन में पद्म सम्मान समारोह 2026 का भव्य आयोजन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया नामचीन हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित

कला और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजस्थान की तीन हस्तियां भी पद्म पुरस्कारों से सम्मानित

जयपुर(नि.सं.)। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार सम्मान समारोह 2026 में देश की नामचीन हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इस अवसर पर राजस्थान के तीन विशिष्ट व्यक्तित्वों को भी वर्ष 2026 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है। इनमें लोक कला और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कलाकार एवं समाजसेवी शामिल हैं। कला क्षेत्र में श्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी और तगाराम भील को, जबकि समाज सेवा के क्षेत्र में स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया गया। राजस्थान के डीग निवासी श्री गफरुद्दीन मेवाती जोगी को मेवाती लोक संगीत और पारंपरिक लोक विधाओं को संरक्षित एवं विश्व स्तर पर पहचान दिलाने के लिए यह सम्मान प्रदान किया गया। वे पिछले कई दशकों से अधिक समय से भपंग वादन की परंपरा को जीवित रखने में जुटे हुए हैं। उन्हें इस लोक शैली का अनूठा कलाकार माना जाता है। भपंग के साथ-साथ वे अलगोजा, चिकारा और जोगी सारंगी सहित करीब 12 पारंपरिक लोक वाद्य यंत्रों में निपुण हैं।

प्रतापगढ़ में दिशा समिति की बैठक

केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

जयपुर(नि.सं.)। प्रतापगढ़ जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सांसद चित्तौड़गढ़ सी.पी. जोशी की अध्यक्षता और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की सह अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में सांसद चित्तौड़गढ़ जिले में संचालित विभिन्न केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम स्वनिधि, एनआरएलएम, पोषण 2.0, एक जिला एक उत्पाद, सामाजिक सुरक्षा योजना, महिला एवं बाली विकास संबंधित योजनाओं, कचरा निस्तारण, जल संरक्षण एवं ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान स्वयं सहायता समूहों को स्वरोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने पर विशेष जोर दिया गया।

प्रभारी मंत्री ने वागदरी तालाब पर किया श्रमदान

वन्दे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कार्यक्रम, पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया

डूंगरपुर(वि.सं.)। जिला प्रशासन की ओर से डूंगरपुर पंचायत समिति की वागदरी पंचायत के वागदरी तालाब पर वन्दे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डूंगरपुर जिले के प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी मुख्य अतिथि रहे। इस दौरान प्रभारी मंत्री खराड़ी सहित जिला कलेक्टर देशलदान, भाजपा नेता बंशीलाल कटारा, जिला परिषद सीईओ हनुमान सिंह राठौड़ और अन्य जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने तालाब पर श्रमदान किया। उन्होंने तालाब को गहरा करने और साफ-सफाई में सहयोग दिया। साथ ही, तालाब के किनारे पौधरोपण करते हुए आमजन को जलाशयों के संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया गया।

प्रतिभागियों से संवाद

युवा नवाचार आधारित सोच के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करें : चूरू प्रभारी सचिव

जयपुर(नि.सं.)। ग्रामीण विकास शासन सचिव व चूरू जिला प्रभारी सचिव कृष्ण कुणाल ने जिला मुख्यालय पर लोहिया महाविद्यालय स्थित इनक्यूबेशन सेंटर में चल रहे इनोवेट चूरू बूट कैंप का पर्यवेक्षण किया और प्रतिभागियों से संवाद करते हुए युवाओं को नवाचार, स्टार्टअप एवं एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। चूरू प्रभारी सचिव कृष्ण कुणाल ने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं के पास असीम संभावनाएं हैं तथा नवाचार आधारित सोच के माध्यम से वे न केवल स्वयं को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, बल्कि अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर सृजित कर सकते हैं। उन्होंने प्रतिभागियों को अपने आइडियाज को व्यवहारिक रूप देने तथा तकनीक एवं कौशल का बेहतर उपयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने कोड चूरू कार्यक्रम में इनरोल बच्चों द्वारा सालासर बालाजी मंदिर के लिए तैयार की गई वेबसाइट की लॉन्चिंग की और वेबसाइट का अवलोकन किया। वेबसाइट बनाने वाले बच्चों को पुस्तकें भेंट कर प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर चूरू जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने बूट कैंप की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को स्टार्टअप, बिजनेस मॉडल, डिजिटल इनोवेशन एवं स्वरोजगार से संबंधित व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

एक साल की मासूम को गर्म सरिए से दागा

निमोनिया हुआ था, परिजन भोपे के पास ले गए; हालत बिगड़ी तो हॉस्पिटल लेकर पहुंचे

भीलवाड़ा(वि.सं.)। मासूम बच्चों की तबीयत खराब होने पर उनका हॉस्पिटल में इलाज करवाने की बजाए भोपे के पास ले जाकर डाम लगवाने की कुप्रथा आज भी जारी है। पुरानी परम्पराओं के नाम पर मासूमों को गर्म सरिए से दागा जा रहा है और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मामला भीलवाड़ा के महात्मा गांधी जिला हॉस्पिटल से सामने आया है। यहां एक साल की बच्ची को निमोनिया की शिकायत होने पर परिजन भोपे के पास ले गए, जहां भोपे ने बच्ची के पेट पर गर्म सरिया(डाम) लगा दिया। दर्द से तड़पती मासूम की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। इसके दो दिन बाद मंगलवार की सुबह मां बच्ची को लेकर जिला हॉस्पिटल पहुंची।

कृषि एवं उद्यानिकी योजनाओं किया निरीक्षण

नवाचार आधारित खेती को बताया कृषक समृद्धि का आधार

जयपुर(नि.सं.)। राज्य सरकार द्वारा संचालित कृषि एवं उद्यानिकी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कृषकों को आधुनिक तकनीकों से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी मंजू राजपाल ने भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी तहसील के गोविंदपुरा ग्राम का दौरा कर विभिन्न कृषि एवं उद्यानिकी योजनाओं के अंतर्गत

किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्षेत्र के प्रगतिशील कृषकों द्वारा अपनाई जा रही उन्नत कृषि तकनीकों, संरक्षित खेती, सूक्ष्म सिंचाई एवं सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान प्रमुख शासन सचिव ने किसान चांता देवी, धनराज माली एवं भंवर माली के खेतों का भ्रमण किया। यहां कृषकों द्वारा उद्यान विभाग की योजनाओं के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग तकनीक एवं संरक्षित खेती को अपनाते हुए मिर्ची, भिंडी,

पत्रकार वार्ता किसान आयोग अध्यक्ष ने डीडवाना-कुचामन में की पत्रकार वार्ता

वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में मीडिया और आमजन की भागीदारी आवश्यक : सी आर चौधरी

जयपुर(नि.सं.)। डीडवाना-कुचामन जिले में जल संरक्षण दिशा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हो गई है। अभियान को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। किसान आयोग के अध्यक्ष सी आर चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण व पारंपरिक जल स्रोतों के रख रखाव के लिए यह अभियान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह केवल एक राजकीय कार्यक्रम नहीं, बल्कि जन-जन का अभियान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जल संरक्षण की थीम पर यह

व्यापक अभियान शुरू किया गया है। 5 जून (विश्व पर्यावरण दिवस) तक अभियान का पहला चरण चलेगा, लेकिन जल संरक्षण को हमारी दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना और जन - जन को इस अभियान जोड़ना इसका प्रमुख उद्देश्य है। किसान आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी अभियान को आमजन तक पहुंचाने में मीडिया की भूमिका सबसे अहम होती है।

उन्होंने अपील की कि मीडिया इस अभियान के संदेश को जन-जन तक ले जाए ताकि लोग इससे जुड़ सकें। इस दौरान जिला प्रभारी सचिव नकाते शिवप्रसाद ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जल स्रोतों की उचित देखरेख, वर्षा पूर्व साफ- सफाई एवं पौधारोपण व जल संरक्षण की गतिविधियां जिला स्तर से ग्राम स्तर की जायेगी और राज्य सरकार की मंशानुसार अभियान में आमजन की भागीदारी से जिले में जल संरक्षण की दिशा में कार्य किये जायेगें।

आश्रय ही नहीं, स्वावलंबन का नया केंद्र: हुनर सीखकर आत्मनिर्भर बन रही बेसहारा महिलाएं

निराश्रित, बेसहारा और प्रताड़ित महिलाओं के लिए उम्मीद की एक नई किरण 'नारी निकेतन'

लोक टुडे। जयपुर

सपनों के टूटने, अपनों के छूटने और सामाजिक प्रताड़ना के अंधकार से निकलकर जब कोई महिला राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के 'नारी निकेतन' (राज्य महिला सदन) की दहलीज पर कदम रखती है, तो उसे सिर्फ एक छत नहीं मिलती, बल्कि मिलता है आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और जीने की नई किरण। आधुनिक समाज में जहां एक ओर विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ जा रहा है, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक उपेक्षा, घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना की शिकार महिलाओं की संख्या भी चिंता का विषय है। ऐसी विकट परिस्थितियों में 'नारी निकेतन' (महिला आश्रय गृह) इन निराश्रित और बेसहारा महिलाओं के जीवन में उम्मीद का एक नया सवेरा बनकर उभर रहे हैं। आज ये केंद्र केवल सिर छुपाने की जगह नहीं, बल्कि महिलाओं के संपूर्ण कायाकल्प और पुनर्वास के सबसे बड़े माध्यम बन चुके हैं।

चारदीवारी से आत्मनिर्भरता तक का सफर :

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य सामाजिक रूप से उत्पीड़ित, अनैतिक परिस्थितियों की शिकार एवं निराश्रित महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना और उनमें नवजीवन का संचार करना है। यहां महिलाओं को सुरक्षित वातावरण में निःशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यहां त्योहारों और सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन भी सामूहिक रूप से होता है, जिससे महिलाओं को अकेलेपन का अहसास न हो। इन्हें एडवांस्ड सिलाई-कढ़ाई और ब्यूटीशियन कोर्स जैसी आधुनिक ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई जाती है।

हर जिले पर नारी निकेतन का संचालन :

मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील नेतृत्व और दूरदर्शी सोच के चलते आज प्रदेश के ये केंद्र महज़ शेल्टर होम नहीं, बल्कि निराश्रित और आश्रयहीन युवतियों की तकदीर बदलने वाली कर्मस्थली बन चुके हैं। वर्तमान में विभाग द्वारा जयपुर संभाग के जिला मुख्यालय पर 150 क्षमता का एक महिला सदन और शेष अन्य संभागों के जिला मुख्यालयों पर 50-50 क्षमता के साथ एक-एक नारी निकेतन संचालित है, जहाँ उनके जीवन को एक नई और सम्मानजनक दिशा दी जा रही है।

11 बेटियों के लिए आए 1900 से अधिक रिश्तें :

इस सकारात्मक बदलाव और लगातार बढ़ते पुनर्वास का सबसे जीवंत उदाहरण हाल ही में राज्य महिला सदन जयपुर में देखने को मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में जब संस्थान की 11 योग्य युवतियों के विवाह के लिए सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी की गई, तो समाज की सोच में एक बड़ा बदलाव नजर आया। इन 11 बेटियों से विवाह के लिए प्रदेशभर से 1900 से अधिक उच्च शिक्षित और सुयोग्य युवकों ने आवेदन किया। विभाग ने केवल आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि पुलिस वेरिफिकेशन और पारिवारिक पृष्ठभूमि की पूरी जांच के बाद ही वरों का चयन किया। इन शादियों का आयोजन किसी रसूखदार परिवार की तरह धूमधाम से किया जाता है, जहाँ स्वयं मुख्यमंत्री और प्रशासनिक अधिकारी 'कन्यादान' करने और आशीर्वाद देने पहुंचते हैं।

महिलाओं के कल्याण पर बढ़ता व्यय :

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री गहलोत ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा महिला सदन एवं नारी निकेतनों में निवासरत 1006 महिलाओं के पुनर्वास और कल्याण पर पिछले ढाई वर्षों में 1613.35 लाख रुपये व्यय किए गए है। इन नारी निकेतनों की आवासनीयों में से 30 से ज्यादा महिलाओ को विवाह के माध्यम से पुनर्वासित किया गया है और 218 महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया है। यह आंकड़े राज्य सरकार की महिलाओं के कल्याण और पुनर्वास के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

अतीत के कड़वे अनुभवों को छोड़ा पीछे, संवर रहे भविष्य :

अतीत के कड़वे अनुभवों को पीछे छोड़कर भविष्य को संवारने का जो काम राजस्थान के नारी निकेतन कर रहे हैं, वह समाज के लिए एक नजीर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की संवेदनशीलता इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यदि सही संरक्षण, सुरक्षा और अवसर मिले, तो समाज की सबसे वंचित महिला भी गरिमा के साथ सिर उठाकर जी सकती है। नारी निकेतन अब बेसहारा महिलाओं के लिए 'सशक्तिकरण का नया और स्थाई पता' बन चुके हैं।

कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने विकास कार्यों का लिया फील्ड फीडबैक

जयपुर।

झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ मंगलवार, 26 मई को क्षेत्र के विस्तृत निरीक्षण दौरे पर निकले। उन्होंने विभिन्न वार्डों में चल रहे एवं पूर्ण हुए विकास कार्यों का स्वयं मौके पर जाकर निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पिछले महीने नगर निगम, जेडीए सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत विभाग, पेयजल विभाग, निगम और अन्य विभागों के अधिकारियों की मीटिंग लेकर सार्वजनिक समस्याओं के त्वरित निदान के आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे और अधिकारियों को ताकीद किया कि आमजन के कामों को तत्परता के साथ पूरा किया जाए। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ का मंगलवार का यह निरीक्षण दौरा उन्हीं निर्देशों की प्रगति की समीक्षा से जुड़ा हुआ था। निरीक्षण के दौरान उन्होंने करणी पैलेस स्थित हाईटेंशन लाइन रोड के नीचे सफाई एवं स्ट्रीट लाइट कार्यों का जायजा लिया। वॉर्ड 50 स्थित रंगोली गार्डन एवं वॉर्ड 53 में महाराणा प्रताप रोड के विकास कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं। वॉर्ड 56 में गांधीपथ, लालरपुरा क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य तथा गिरधारीपुरा पंपिंग स्टेशन के पीछे सड़क निर्माण कार्य को भी पूरा कर लिया गया है। वॉर्ड 56 से 59 तक धाबास हाईटेंशन लाइन क्षेत्र के नीचे डब्ल्यूएमएम सड़क निर्माण कार्य भी पूर्ण हुआ। सामान्यतः हाईटेंशन लाइन के नीचे सड़क निर्माण की अनुमति नहीं होती, लेकिन क्षेत्रवासियों की आवाजाही में हो रही परेशानी को देखते हुए कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने विशेष पहल कर डब्ल्यूएमएम सड़क निर्माण करवाया। मंगलवार को उन्होंने स्वयं मौके पर पहुंचकर इस कार्य का निरीक्षण किया। वॉर्ड 62 में संजय नगर, शनिमंदिर के निकट डिवाइडर सफाई कार्य को भी पूरा किया गया है। साथ ही कालवाड़ रोड पर 206 बीघा क्षेत्र में मैकेनाइज्ड ट्रान्सफर स्टेशन स्थापित करने के दिए निर्देश 7 झोटवाड़ा क्षेत्र में लगातार हो रहे विकास कार्यों और समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर जनता में कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ की सक्रिय कार्यशैली की व्यापक चर्चा है। जनता ने कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ की जनहितकारी सोच, त्वरित निर्णय क्षमता और जमीनी कार्यशैली की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया।

दिया कुमारी का संदेश - कार्यकर्ता संगठन और सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएं

लोक टुडे। जयपुर

जयपुर देहात दक्षिण भाजपा द्वारा पदमपुरा में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान 2026 में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संगठन और सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने का संदेश दिया। प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार गरीब, किसान, महिला और युवा वर्ग के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है और इन योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।

दिया कुमारी ने मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भाजपा केवल सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि सेवा, सुशासन और राष्ट्र प्रथम की विचारधारा पर कार्य करती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे घर-घर जाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को स्वयं भी योजनाओं की पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि आमजन को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कार्यक्रम में भाजपा के कई जनप्रतिनिधि, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे।

एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक में डिपो मैनेजर गिरफ्तार

एग्जाम से पहले बेटा-बेटी को पढ़ाया था लीक पेपर, अपनी गाड़ी से एग्जाम दिलाने लाया था जयपुर

लोक टुडे। जयपुर

एसआई भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में एसओजी ने आरएसबीसीएल के डिपो मैनेजर को मंगलवार दोपहर अरेस्ट किया है। आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा से मिले पेपर को एग्जाम से पहले बेटा-बेटी को पढ़ाया था। अपनी गाड़ी से बेटा-बेटी को जयपुर लाकर एग्जाम दिलवाकर पास करवाया था। एसओजी टीम फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है। एडीजी (एसओजी) विशाल बंसल ने बताया- एसआई भर्ती परीक्षा-2021 पेपर लीक मामले में आरोपी लोकेन्द्र पण्डया (58) निवासी वरदा डूंगरपुर को अरेस्ट किया गया है। वह डूंगरपुर के सागवाड़ा में राजस्थान राज्य बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएसबीसीएल) में डिपो मैनजर की पोस्ट पर है। एसआई भर्ती परीक्षा-2021 की लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न-पत्रों के प्रश्नोत्तर आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा से कुंदन कुमार पण्डया ने प्राप्त किए थे। कुंदर कुमार पण्डया के भाई लोकेन्द्र पण्डया ने भी परीक्षा से पहले कुंदन की बेटी रिद्धी पण्डया के साथ-साथ अपने बेटे नैतिक पण्डया और बेटी नेहा पण्डया को पढ़ाया था। लीक पेपर पढ़ाकर तैयारी करवाने के बाद अपनी गाड़ी से जयपुर साथ लाकर लिखित परीक्षा दिलवाई थी। लीक पेपर पढ़कर नैतिक को हिन्दी सब्जेक्ट में 200 में 143.33 नंबर और सामान्य ज्ञान में 200 में से 147.20 नंबर मिले थे। लोकेन्द्र की बेटी नेहा को हिन्दी में 200 में से 158.89 और सामान्य ज्ञान में 200 में से 153.46 नंबर मिले थे। लीक पेपर से तैयारी कर दोनों भाई-बहन ने लिखित परीक्षा पास की थी। नैतिक और नेहा दोनों को पूर्व में 10 जुलाई 2025 को अरेस्ट कर जेसी भेजा जा चुका है। मामले में आरोपी पिता लोकेन्द्र पण्डया को मंगलवार दोपहर अरेस्ट किया गया है। एसओजी की ओर से कोर्ट में पेश कर दो दिन का रिमांड लिया गया है। मामले में अब तक 142 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

प्रदेश में जल संरक्षण को मिलेगी नई रफ्तार

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के लिए 688 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी

जयपुर

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत जल संरक्षण एवं भू-जल संवर्धन कार्यों को गति देने के लिए द्वितीय एवं तृतीय चरण के लिए 688.28 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की हैं। अभियान के द्वितीय चरण के लिए जल संरक्षण उपकर निधि से 488.28 करोड़ रुपये तथा तृतीय चरण के लिए राज्य निधि प्रावधान से 200 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत कर जारी की गई है।

अभियान के तहत अब तक कुल 988.28 करोड़ रुपये जारी

जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग की निदेशक एवं पदेन विशिष्ट शासन सचिव कल्पना अग्रवाल ने बताया कि जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के तहत प्रदेशभर में जल संरक्षण, जलग्रहण विकास, भू-संरक्षण एवं जल संवर्धन से जुड़े कार्यों को व्यापक स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा 688.28 करोड़ की राशि जारी कर अभियान को नई गति दी गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 के द्वितीय चरण के लिए इससे पूर्व भी 300 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा अभियान के तहत अब तक विभिन्न चरणों में 988.28 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। अभियान के द्वितीय चरण के लिए अब अतिरिक्त 488.28 करोड़ रुपये जारी होने से अभियान को और अधिक मजबूती मिलेगी।

सीईटीपी स्थापना की हैम मॉडल आधारित नई योजना लागू

जयपुर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को आर्थिक संबल प्रदान करते हुए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना लागू की गई है। इसके तहत प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) की स्थापना के लिए 150 करोड़ रुपये तक अनुदान दिया जाएगा। रीको एवं नॉन-रीको औद्योगिक क्षेत्रों में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर आधुनिक तकनीक 'जीरो लिक्विड डिस्चार्ज' वाले प्लांट स्थापित होंगे। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा योजना की गाइडलाइन भी जारी कर दी है।

दोबारा उपयोग में आ सकेगा उपचारित जल

उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) शिखर अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले इस अनुदान से प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को काफी फायदा होगा। वर्तमान में प्रदेश में ज्यादातर औद्योगिक इकाइयों में अपशिष्ट जल का प्रबंधन व्यक्तिगत एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) या क्लस्टर-स्तर के सीईटीपी के माध्यम से किया जाता है। अधिकांश सीईटीपी में रीसाइक्लिंग प्रणाली की कमी है, जिससे पानी का पुनः उपयोग सीमित हो जाता है, लेकिन इस नई योजना के तहत आधुनिक तकनीक 'जीरो लिक्विड डिस्चार्ज' वाले प्लांट लगने से जल को दोबारा काम में लिया जा सकेगा।

प्रभावी संचालन के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर मिलेगा अनुदान

अग्रवाल ने बताया कि इस योजना के तहत सीईटीपी के निर्माण और संचालन के लिए कलस्टर की उद्योग इकाइयों द्वारा एक एसपीवी (स्पेशल पर्पज व्हीकल) बनानी होगी। राज्य सरकार द्वारा परियोजना लागत का 80 प्रतिशत या अधिकतम 150 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। मात्र 20 प्रतिशत राशि ही एसपीवी को वहन करनी होगी। सीईटीपी के प्रभावी संचालन के लिए हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर अनुदान दिया जाएगा। इसके तहत कार्य के चरणों के अनुसार भुगतान किया जाएगा, 60 प्रतिशत अनुदान 20-20 प्रतिशत की तीन किस्तों में और 20 प्रतिशत राशि 20 वर्षों में उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि प्लांट का लंबे समय तक प्रभावी संचालन सुनिश्चित हो सके।

एंबुलेंस की टक्कर से युवक की मौत पर 1.47 करोड़ मुआवजा

लोक टुडे। जयपुर

जयपुर महानगर प्रथम की मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण-2 ने एंबुलेंस की टक्कर से मौत के मामले में युवक के परिजनों को 1.47 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। परिजनों के दावे पर अ?धिकरण की न्यायाधीश नुसरत बानो ने ड्राइवर बृज किशोर, वाहन स्वामी बचन सिंह और बीमा कंपनी को संयुक्त और पृथक रूप से राशि चुकाने का आदेश दिया। करीब 7 साल पहले 9 मार्च 2019 को जगतपुरा के अपेक्स सर्किल के पास एंबुलेंस से टक्कर लगने के बाद अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार की मौत हो गई थी। सुनवाई के दौरान बीमा कंपनी ने तर्क दिया कि शुरुआती एफआईआर अज्ञात वाहन के खिलाफ दर्ज की गई थी। बाद में मिलीभगत कर एंबुलेंस को झूठा शामिल किया गया।

हालांकि कोर्ट ने पाया कि हादसे के समय मौके पर मौजूद गवाह ने दुर्घटना के तुरंत बाद मृतक के मोबाइल से उनके रिश्तेदार को सूचना दी थी और एंबुलेंस का नंबर नोट कराया था। हादसे के अगले ही दिन पुलिस को वाहन नंबर सहित विस्तृत प्रार्थना-पत्र सौंप दिया गया था। दुर्घटना के बाद घायल को उसी एंबुलेंस से अस्पताल ले जाने का वीडियो भी एसएमएस अस्पताल के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुआ था।

खुद कृषि मंत्री ग्राउंड पर... अधिकारियों की कार्यशैली पर खड़े हुए सवाल !

बीज माफिया पर किरोड़ी का सर्जिकल स्ट्राइक, चौमूं में नकली बीज फैक्ट्री का भंडाफोड़

लोक टुडे। जयपुर

राजस्थान में किसानों की मेहनत, उम्मीदों और खेतों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले बीज माफियाओं पर अब सरकार ने बड़ा प्रहार कर दिया है। जयपुर के चौमूं इलाके में कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने खुद मोर्चा संभालते हुए नकली बीजों के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। चौमूं के सिल्वर पार्क रीको एरिया में चल रही फैक्ट्रियों पर हुई इस अचानक कार्रवाई ने पूरे प्रदेश में बीज माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया है।

कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा अपनी टीम के साथ अचानक 'एग्रो जेनिक्स क्रॉप साइंस' और 'जीएम एग्रो इंडस्ट्रीज' नाम की इकाइयों में पहुंचे, जहां अवैध तरीके से मूंगफली बीजों की पैकिंग का खेल चल रहा था। जांच में सामने आया कि साधारण और घटिया क्वालिटी की मूंगफली को मशीनों से प्रोसेस कर उसे हाई क्वालिटी बीज बताकर बाजार में उतारने की तैयारी की जा रही थी। मौके से किसान-510, SG-551 और RG-578 जैसे नामों वाले लाखों खाली बैग, हजारों तैयार पैकेट, करीब 60 लाख खाली बोरियां और लगभग 2 लाख मूंगफली की बोरियां बरामद हुईं। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री में लगी हाईटेक मशीनों और पैकिंग यूनिट्स को देखकर साफ हो गया कि किसानों को ठगने का यह धंधा बेहद संगठित तरीके से लंबे समय से चल रहा था। चमकदार पैकेटों में नकली और अमानक बीज भरकर उन्हें असली ब्रांड के नाम पर बेचने की तैयारी की जा रही थी, ताकि किसान ऊंचे दाम देकर इन्हें खरीदें और बाद में खराब फसल की मार झेलें। मीणा ने कार्रवाई के बाद बेहद सख्त शब्दों में कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि बीज माफिया केवल किसानों की फसल बर्बाद नहीं कर रहे, बल्कि उनके सपनों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय बढ़ाने के मिशन पर भी हमला कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि इस पूरे नेटवर्क से जुड़े हर व्यक्ति की जांच होगी और दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई केवल चौमूं तक सीमित नहीं है। प्रदेशभर में कृषि विभाग और प्रशासन ने विशेष अभियान चलाते हुए जोधपुर, बीकानेर, सीकर और चूरू समेत कई जिलों में एक साथ दबिश दी है। विभाग अब फैक्ट्रियों के लाइसेंस, सप्लाई चैन, रिकॉर्ड और बाजार में भेजे गए बीजों की जांच में जुट गया है। इस कार्रवाई के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर किसानों के नाम पर करोड़ों का यह गोरखधंधा इतने लंबे समय से किसके संरक्षण में चल रहा था। फिलहाल चौमूं की इस कार्रवाई ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अब किसानों के साथ धोखा करने वालों पर सरकार सीधी और सख्त कार्रवाई के मूड में है।

जब 'बाबा' ने संभाली कमान, कांपे माफिया

राजस्थान की भजनलाल सरकार में अपनी बेबाक और जमीनी कार्यशैली के लिए 'बाबा' नाम से मशहूर कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा इन दिनों एक्शन मोड में हैं। जब सरकारी दफ्तरों और फील्ड में बैठे प्रशासनिक अफसरों की नाक के नीचे गरीब किसानों के पसीने की कमाई को लूटा जा रहा था, तब किसी एसी कमरे के आदेश का इंतजार किए बिना खुद मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने ग्राउंड जीरो पर मोर्चा संभाल लिया।

प्रशासनिक सुस्ती ; क्या कर रहा पूरा विभाग :

राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा खुद ग्राउंड पर उतरकर लगातार औचक निरीक्षण और छापेमारी कर रहे हैं, क्योंकि राज्य में किसानों के हक पर डाका डालने वाले भ्रष्टाचार, नकली खाद-बीज के अवैध काले कारोबार और एसबीआई की शाखाओं में बीमा घोटाला जैसी गंभीर शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में जयपुर के पास चौमूं, हनुमानगढ़ और प्रदेश के अन्य हिस्सों में कृषि विभाग के साथ मिलकर की गई ताबड़तोड़ छापेमारी ने प्रशासनिक सुस्ती और स्थानीय स्तर पर बैठे अधिकारियों की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक - [illegible] लक्ष्मी नगर, [illegible], अजमेर रोड, जयपुर - 302006 से मुद्रित [illegible] नंबर 19, [illegible] नगर, जयपुर (राज.) [illegible]